हाथ बदलेगा हालात

जम्मू और कश्मीर घोषणापत्र-2024

आप सभी की खिदमत में पेश है आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणापत्र।

हमारा लक्ष्य रूढ़िवाद और कट्टरतावादी ताकतों को हराना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन या हमारे संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया और जिनका एकमात्र उद्देश्य हमारे हज़ारों साल की विरासत और विविधता में एकता के भाव से भरी राष्ट्रीयता की भावना को चोट पहुंचाना है। विभाजनकारी ताकतों से लड़ना हमारा परम कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ सहयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है।

एक अपील

यह बुनियादी बातों की ओर लौटने का समय है; वे बुनियादी बातें जिन्होंने हमारे सार तत्व को बनाया है; वे बुनियादी बातें जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी; वे बुनियादी बातें जिन्होंने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरे भारत का निर्माण किया है। यह हमारे लिए उन बुनियादी मूल्यों को फिर से स्थापित करने का समय है जिन्होंने भारत की एकता को सुनिश्चित किया है।

सबसे दुखद बात तो यह है कि हमारे नागरिकों का प्रधानमंत्री और उनकी अप्रभावी सरकार की बातों से विश्वास उठ गया है। प्रधानमंत्री ने हमें सिर्फ बड़े-बड़े वादे, खोखले नारे, फेल कार्यक्रम एवं नीतियां, झूठे आंकड़े, भ्रष्टाचार और भय, धमकी एवं नफरत का माहौल दिया है।

गहरे संकट से भरे इस दौर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों को एकमात्र विकल्प उपलब्ध कराती है। यह एक विशिष्ट विकल्प है जो हमारे लोगों के लिए सत्य, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्म-सम्मान और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर दृढ़ है। हम भारत को मजबूत और एकजुट तथा एक न्यायपूर्ण एवं समृद्ध समाज बनाने का वादा करते हैं।

हमारा घोषणापत्र, हमारे विज़न की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो कि आंतरिक आवाज को सुनना है। यह किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सामूहिक आवाज है। हमने इनपुट्स के लिए सभी संभावित उपकरणों - वेबसाइट, व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन पिटीशनंस और नागरिकों, विशेषज्ञों, स्टेकहोल्डर्स और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का इस्तेमाल किया है। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणापत्र समिति ने विभिन्न लोगों के साथ चर्चा की।

यह हमारी प्रतिबद्धता है।

कांग्रेस वादा करती है और अपने वादों को निभाती भी है।

सैफुद्दीन सोज़
अध्यक्ष, घोषणापत्र समित

शासन

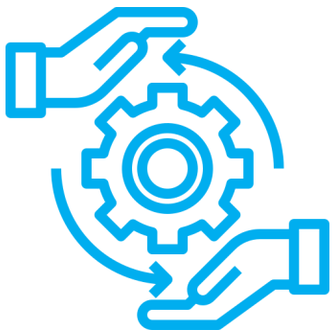

1. हम यह सुनिश्चित करते हुए समावेशी और जवाबदेह शासन प्रदान करेंगे कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दे।

2. हम दरबार मूव के पक्ष में पहले विधानसभा सत्र का पहला प्रस्ताव पारित करके श्रीनगर और जम्मू में क्रमशः ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियों की 149 साल की परंपरा को बहाल करेंगे।

3. हम नौकरियों, सरकारी अनुबंधों, भूमि आवंटन और प्राकृतिक संसाधन रियायतों के लिए जम्मू-कश्मीर के निवासियों को पहली प्राथमिकता देंगे।

4. हम भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करेंगे और पिछले दस वर्षों में कथित तौर पर घोटालों में शामिल सभी अधिकारियों - सेवारत और सेवानिवृत्त - के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए पहले 100 दिनों के भीतर एक लोकायुक्त का गठन करेंगे।

5. हम सभी निर्वाचित विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सशक्त करेंगे ताकि लोगों की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके।

6. हम विधान परिषद को बहाल करेंगे और उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र जोड़ेंगे जिनका विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है जैसे कि ओबीसी, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, पेंशनभोगी, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि।

7. हम 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराएंगे। हम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल को शामिल करेंगे।

8. छह महीने के भीतर एक निष्पक्ष और पारदर्शी भूमि नीति तैयार होने तक गरीब लोगों और किसानों - विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों - के कब्जे वाली भूमि से उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। छह माह के भीतर वन में रहने वाले लोगों को वन अधिकार कानून के तहत अधिकार भी दिए जाएंगे।

9. हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम को अक्षरश: लागू करेंगे और सिस्टम की खामियों पर अंकुश लगाएंगे।

10. हम पीओजेके विस्थापित व्यक्ति और शरणार्थी बोर्ड बनाएंगे और उनकी बेहतरी सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 2014 के वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालेंगे जैसा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी और संसद की स्थाई समिति ने जिसका समर्थन किया था:

- हम 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित व्यक्तियों और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित राज्य भूमि एवं विस्थापितों की संपत्तियों को बेचने और स्थानांतरित करने के अधिकार सहित सभी अधिकार प्रदान करेंगे।

- हम 1947 के अपंजीकृत और बहिष्कृत विस्थापितों और शरणार्थियों के वास्तविक मामलों की फिर से जांच करेंगे और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें भूमि अधिकार और वित्तीय पैकेज प्रदान करेंगे।

- हम विस्थापितों और शरणार्थी बस्तियों एवं शिविरों को नियमित करेंगे।

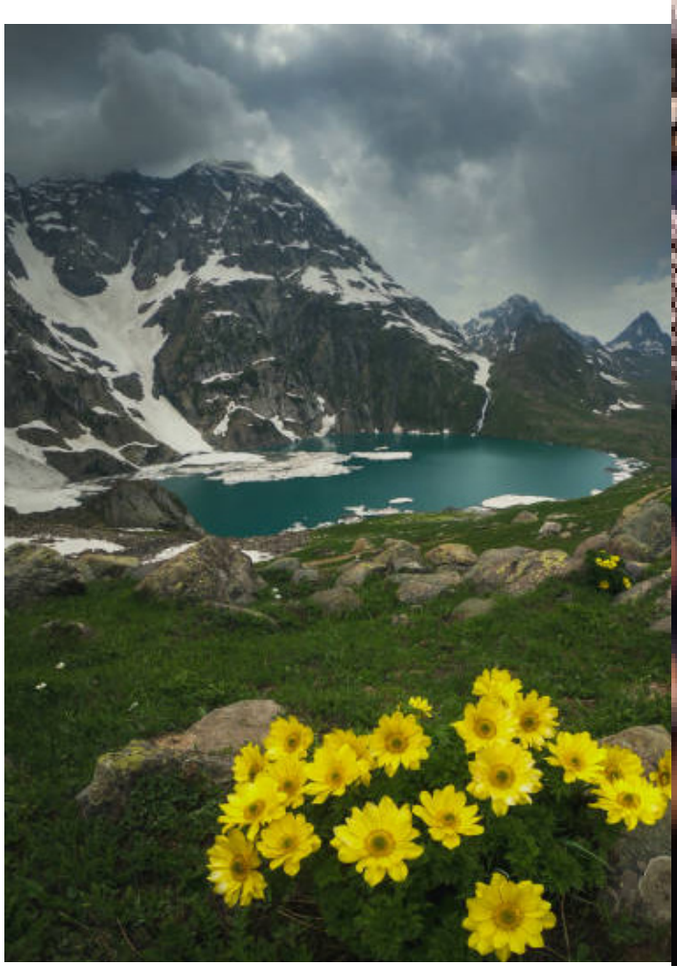

रोज़गार

1. हम योग्य युवाओं को एक वर्ष के लिए प्रति माह 3,500 रूपए तक का बेरोज़गारी भत्ता देंगे।

2. हम विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरेंगे और लंबित सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए पहले 30 दिनों के भीतर एक नौकरी कैलेंडर जारी करेंगे।

3. आवेदकों को वर्ष में केवल एक बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. हम स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए जिला भर्ती बोर्डों के माध्यम से जिला कैडर के पदों को भरेंगे।

5. हम शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को भरेंगे।

6. हम छह महीने में रोकी गई और लंबित आरईटी को मंजूरी देंगे।

7. हार्ड जोन्स में बंद स्कूलों को तुरंत एडहॉक के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके बाद नई भर्ती नीति बनाई जाएगी।

8. हम जम्मू-कश्मीर पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन सुरक्षा बल के लिए विशेष सीमा भर्तियों और ऑन-द-स्पॉट भर्तियों को पुनर्जीवित करेंगे।

9. हम एक विशेष पर्यटक सुरक्षा एवं कल्याण बल का गठन करेंगे।

10. हम बेरोजगार इंजीनियरों के ग्रुप्स को 30% कॉन्ट्रैक्ट देने की योजना को पुनर्जीवित करेंगे।

11. हम रोजगार कार्यालयों को नौकरी प्लेसमेंट केंद्र और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में बदलेंगे।

12. हम अनुचित और अनावश्यक परेशानी को रोकने के लिए सभी सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट और अन्य उद्देश्यों के लिए सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाएंगे।

लोक कल्याणकारी कार्य

मौजूदा समय में मुफ़्त राशन का आवंटन 5 किलो है। हम इसे बढ़ाकर 11 किलो करेंगे।

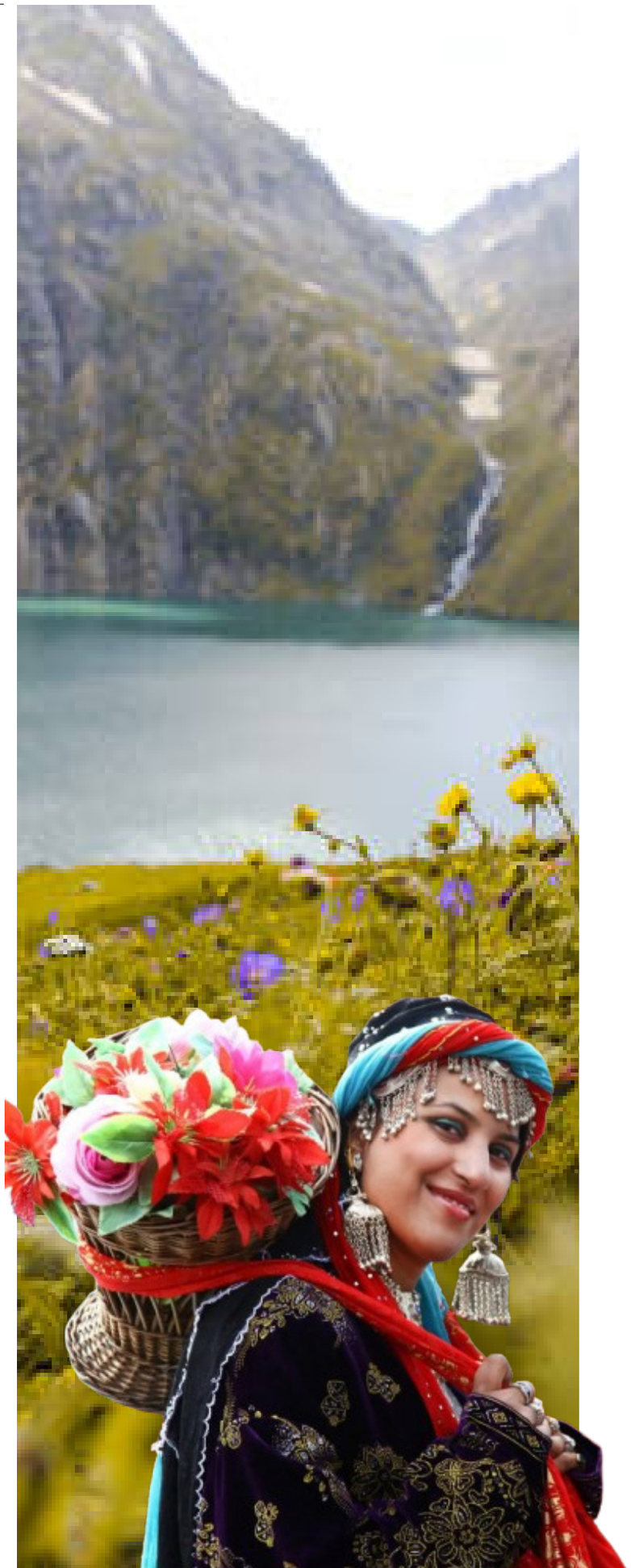

महिला

1. महिला सम्मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे।

2. सखी शक्ति के तहत हम प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे।

3. हम छात्राओं के लिए एक बेटी छात्रवृत्ति योजना प्रदान करेंगे।

4. हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य का हिस्सा दोगुना करेंगे और केंद्र सरकार पर भी अपना हिस्सा दोगुना करने के लिए दबाव डालेंगे।

5. हम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने और उन्हें सहायता एवं सलाह देने के लिए योग्य एचएनएम कार्यकर्ताओं को बुनियादी कानूनी प्रशिक्षण देकर आईसीडीएस को मजबूत करेंगे।

6. हम प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस कक्ष स्थापित करेंगे।

7. हम पंचायतों को महिला क्लब और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

शिक्षा

1. सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए, हम ब्लॉक स्तर पर व्यापक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक मॉडल स्कूल बनाएंगे।

2. हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी समान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में मॉडल बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे।

3. हम शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर खाली पदों को भरेंगे।

4. हम कमजोर वर्गों के छात्रों पर विशेष जोर देते हुए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती कोचिंग सुनिश्चित करेंगे।

5. हम सीयूईटी प्रणाली पर दोबारा विचार करने सहित उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगे।

6. हम शैक्षणिक संस्थानों से आने-जाने वाले विद्यार्थियों को सस्ती परिवहन सेवा मुहैया कराएंगे।

7. हम विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनाएंगे।

8. हम भर्तियों और नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों से साल में केवल एक बार परीक्षा शुल्क लेने का प्रावधान करेंगे।

9. हम प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवाओं को आयु में एक बार की छूट देंगे।

10. हम युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उच्च विद्यालयों में अंशकालिक सेल के साथ आईटीआई में कौशल विकास केंद्र जोड़ेंगे।

किसान और कृषि

1. हम भूमिहीन, किराए पर खेती करने वाले एवं भूमि मालिक कृषक परिवारों को प्रति वर्ष अतिरिक्त 4,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करेंगे।

2. हम राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 साल के पट्टे की व्यवस्था करेंगे।

3. हम सेब फसल के लिए 72 रुपए/ किलोग्राम न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे।

4. हम प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100% फसल बीमा प्रदान करेंगे।

5. हम जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए 100% सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला-स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करेंगे।

6. बिचौलियों की लागत कम करने के लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में थोक अनाज बाजार बनाएंगे।

7. हम पूरे वर्ष के लिए वसूले जाने वाले बिजली शुल्क के मुद्दे का समाधान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जितना इस्तेमाल हो, सिर्फ उतने का ही भुगतान करना पड़े।

8. हम किसानों को गारंटर की आवश्यकता के बिना मॉर्गेज पर ट्रैक्टर ऋण प्रदान करेंगे।

9. हम घरेलू उपयोग वाले स्टेशनों पर पंप सेट्स का बोझ कम करने के लिए सीमावर्ती सिंचाई बेल्ट में अलग रिसीविंग स्टेशन की मांग पर विचार करेंगे।

10. हम रेशम मिशन शुरू करके रेशम उत्पादन क्षेत्र को और बढ़ावा देंगे, जिसकी जम्मू-कश्मीर में काफी संभावनाएं हैं।

11. हम ग्रामीण विकास के लिए भेड़, बकरी और मुर्गी पालन क्षेत्रों पर उचित ध्यान देंगे।

स्वास्थ्य

1. हम सभी को इलाज, जांच और दवाओं सहित 25 लाख का बीमा कवरेज देंगे।

2. हम हर तहसील में एम्बुलेंस से लैस मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से 30 मिनट में यूनिवर्सल, सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे।

3. हम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करने एवं डॉक्टरों की तेजी से भर्ती सुनिश्चित करने के उपाय बताने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेंगे।

4. हम एम्स जैसे संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे।

सामाजिक न्याय

कांग्रेस पिछले सात दशकों में पिछड़े एवं उत्पीड़ित वर्गों और जातियों की प्रगति का पक्षधर रही है और उनकी बेहतरी के लिए काम करती रही है। लकिन, भेदभाव अभी भी एक वास्तविकता है। इसे समाप्त करने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता है।

1. हम डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के संविधान में निहित एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।

2. हम प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे की जांच करेंगे।

3. हम भारत के संविधान के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।

4. हम एससी, एसटी और ओबीसी के आवास के लिए राज्य भूमि उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता की जांच करेंगे।

5. हम एसटी के अलावा एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हॉस्टल निर्माण करने पर विचार करेंगे।

6. हम ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति तुरंत बहाल करेंगे।

7. हम केंद्रीय सूची में शहरी कुम्हारों, नाई, धोबी और तेली को अलग करने के मुद्दे को संबोधित करेंगे।

8. हम ओबीसी आयोग में एक ओबीसी सदस्य को शामिल करने की दिशा में क़दम बढ़ाएंगे।

9. परिषद बहाल होने पर हम शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और विधान परिषद में ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे।

10. हम आदिवासी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी वन अधिकार अधिनियम के क्लेम्स पर तेजी से काम करेंगे।

11. हम अपर्याप्त तंबूओं के स्थान पर बने हुए शेड लगाएंगे ताकि प्रवासी जनजातीय आबादी मौसमी स्कूलों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना कर सकें और उनमें कई वर्ग चलाए जा सकें।

12. हम प्रवास अवधि के दौरान आदिवासी परिवारों के अनुपस्थित रहने पर भी लगाए जाने वाले बिजली शुल्क के मुद्दे को संबोधित करेंगे।

13. हम फंड्स का पूरी तरह से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ-साथ जनजातीय प्लान भी तैयार करेंगे।

14. हम सोलर लाइट का उपयोग करके दूरदराज के गांवों और घरों में 100% विद्युतीकरण को बढ़ावा देंगे।

वन के नजदीक वाले गांवों के लिए वन अधिकार

जम्मू और कश्मीर का समृद्ध वन क्षेत्र स्थानीय लोगों द्वारा सबसे अच्छी तरह संरक्षित होता है। लेकिन, उन्हें इन वनों के लाभों से वंचित रखा जाता है। सरकार इस पर विचार करेगी:

1. हम पुराने वन डिपो को फिर से खोलेंगे और स्थानीय लोगों को देवदार और चीड़ की लकड़ी तक पहुंच की इजाज़त देंगे।
2. हम गैर-इमारती वन उपज नीति के तहत जंगल के किनारे के ग्रामीणों को जड़ी-बूटियों, गिरी हुई लकड़ी और चराई पर अधिकार देंगे।

अल्पसंख्यक

1. कश्मीरी पंडितों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम को पुनर्जीवित करके उसे शब्दश: लागू किया जाएगा।

2. हम विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी एवं पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु ठोस कदम उठाएंगे।

3. हम प्रवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और उपाय करेंगे।

4. हम उनके पवित्र तीर्थस्थलों, स्थानों और विरासत की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करेंगे और इस तरह उनकी धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं का सम्मान करेंगे।

5. पहले 100 दिनों के भीतर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जायेगी।

6. जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में पंजाबी को शामिल करने की मांग पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाएगा।

पेंशन

1. हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संभावित तरीके तलाशेंगे।
2. हम वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन बढ़ाएंगे।
3. अनाथ बच्चों की मासिक सहायता शुरू की जाएगी।
4. हम डोर-स्टेप सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाकर इसे परेशानी मुक्त और सरल बनाएंगे।

नंबरदार/चौकीदार

हम नंबरदारों और चौकीदारों का मानदेय बढ़ाएंगे और उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों की समीक्षा करेंगे।

बॉर्डर निवासी

1. हम सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सीमा क्षेत्र कल्याण और विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे।

2. राज्य सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों के लिए भूमि मुआवजे और सेना द्वारा ली गई ईपी भूमि पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे।

3. हम बहुत पुराने हो चुके बंकरों को ठीक-ठाक करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सीमावर्ती निवासियों के लिए इस्तेमाल के योग्य हों। साथ ही शिकायतों की समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे।

4. हम सुरक्षित क्षेत्रों में सीमावर्ती निवासियों के भवनों का निर्माण करेंगे।

5. हम सीमा पार से होने वाली पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण उनके प्रवास की अवधि के दौरान लंबित बिजली बिलों की शिकायत का समाधान करेंगे।

6. हम वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के निवासियों के आरक्षण कोटा को अलग करने की मांग की जांच करेंगे।

वकील और पत्रकार

1. हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब और मीडिया सेंटर स्थापित करेंगे।
2. हम पत्रकारों के लिए यात्रा रियायतों की मांगों पर विचार करेंगे।
3. हम 2022 से बंद पड़ी पत्रकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे।
4. हम पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन पॉलिसी पर विचार करेंगे।
5. हम सरकारी विज्ञापन दरों की दोबारा जांच करेंगे।
6. हम न्यायालय परिसर में वकीलों और वादी जनता के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेंगे।
7. हम कम से कम समय में बार के प्रतिनिधियों के परामर्श से अधिवक्ताओं के कल्याण उपायों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे।

नारकोटिक ड्रग्स और नशीले पदार्थ

1. सरकार ड्रग्स के ख़तरे के खिलाफ युद्धस्तर पर काम शुरू करेगी जिससे जम्मू-कश्मीर के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

2. हम प्रभावित युवाओं के लिए आधुनिक नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेंगे।

3. हम भाजपा सरकार की मदद से हर कोने में बढ़ती शराब की दुकानों को सख्ती से नियंत्रित करेंगे।

4. हम एक्साइज पॉलिसी की भी समीक्षा करेंगे।

पर्यटन

1. पर्यटन क्षेत्र को उद्योग घोषित किया जाएगा।

2. हम इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उचित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अधिक सुंदर स्थानों एवं अज्ञात स्थलों का विकास करेंगे।

3. हम जम्मू शहर में झील सौंदर्यीकरण परियोजना को कम से कम समय में पूरा करेंगे।

4. हम उत्तर बानी, परमंडल, राजौरी-पुंछ, ऊपरी कठुआ, चिनाब घाटी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जम्मू संभाग की अविकसित और अज्ञात पर्यटन संभावनाओं का विकास करेंगे।

5. हम उचित परिवहन शुल्क सुनिश्चित करने सहित पर्यटक परिवहन सुविधाओं को विनियमित करेंगे।

6. हम ट्रांसपोर्टस, टट्टूवालों, गाइड्स और स्लेज श्रमिकों को रेगुलेट करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक उचित नीति अपनाएंगे।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

1. मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक जीवन रेखा रही है, विशेष रूप से महामारी के दौरान। हम सर्दियों के महीनों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ हटाने को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं।

2. विश्वसनीय नेटवर्क कवरेज उपलब्ध होने तक हम अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति और फेस ऑथेंटिकेशन को वापस लेंगे।

3. हम वेंडर्स को समय पर भुगतान और योजना को संचालित करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।

विद्युत एवं विद्युत परियोजनाएं

1. राज्य में उत्पादित जलविद्युत पर पहला अधिकार जम्मू-कश्मीर का होगा। इस बिजली के साथ हम पूरे जम्मू और कश्मीर में 24 x 7 बिजली की गारंटी देने का लक्ष्य रखेंगे।

2. हम गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे।

3. हम जम्मू-कश्मीर में एनएचपीसी जलविद्युत परियोजनाओं की वापसी के लिए तत्परता के साथ प्रयास करेंगे।

4. एनएचपीसी को जम्मू-कश्मीर के लिए पनबिजली परियोजनाओं वाले क्षेत्र के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में निवासियों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।

5. आम सहमति बनने तक सरकार स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाएगी।

6. हम परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्लैट दरों में संशोधन करेंगे।

7. हम सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ावा देंगे एवं लोगों को ग्रिड पर निर्भरता से बाहर निकालने और ग्रिड ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करेंगे।

8. सरकार बिजली पारेषण घाटे को कम करेगी और नियमित भुगतान करने वाले ईमानदार उपभोक्ताओं को समय-समय पर प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

9. हम घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लंबित बिलों पर माफी देने पर विचार करेंगे।

10. जहां भी संभव हो छोटे हाइड्रो प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे।

11. हम कालाकोटे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पुनरुद्धार सहित थर्मल पावर परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशेंगे।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

1. बदलते मौसम के मिज़ाज के अनुकूल होने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए हम जलवायु प्रतिरोधी कृषि एवं टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना।

2. हम व्यापक जल प्रबंधन और प्रदूषण-विरोधी उपायों के माध्यम से जल निकायों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना।

3. हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु सहनशीलता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे एवं सौर ऊर्जा और वनीकरण जैसी हरित पहल का विस्तार करना।

पूर्व सैनिक

1. हम ईसीएचएस सुविधाओं, सीएसडी आइटम्स पर कर छूट और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए सीएसडी सुविधाओं के विस्तार सहित पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्धसैनिक बलों के मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान देंगे।

2. हम विभिन्न स्थानों पर सैनिक भवन के निर्माण पर विचार करेंगे।

सड़कें, पुल और सुरंगें

1. हम विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सड़क संपर्क को विकसित करेंगे एवं इसमें सुधार करेंगे।

2. हम केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों पर सुरंगों और पुलों के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे, जिसमें वैकल्पिक रूप से सभी मौसम के लिए जम्मू-श्रीनगर कनेक्टिविटी के लिए मुगल रोड पर सुरंग, कुपवाड़ा से करनाह, बांदीपुरा से गुरेज तक सुरंग एवं ऐसे अन्य लिंक शामिल हैं।

रेलवे

1. हम जम्मू-पुंछ, कटरा-शिवखोरी विस्तार, कठुआ-महानपुर-भसोली और भद्रवाह-किश्तवाड़ कनेक्शन जैसी उपेक्षित रेलवे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे।

2. हम जम्मू में डीआरएम कार्यालय, हीरानगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने और कोविड-19 के दौरान कठुआ और जम्मू के बीच बंद कर दी गई रेल सेवा को फिर से बहाल करने की मांग को आगे बढ़ाएंगे।

उद्योग

1. हम स्थानीय उद्यमियों, विशेष रूप से रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई

पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति की समीक्षा करेंगे। हम देश के बाकी हिस्सों से भी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

2. हम आर्थिक विकास और नौकरियों के सृजन के दोहरे उद्देश्य के साथ स्थानीय उद्योगों के लिए संपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे।

3. हम बाहरी उद्योगों को अब तक हुए मनमाने तरीके से भूमि आवंटन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएंगे।

4. लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए खतरनाक उद्योगों की स्थापना को रेगुलेट किया जाएगा।

5. सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी।

6. हम अनुबंध श्रम के मामले में श्रम सुरक्षा और कल्याण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

7. हम हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों और बानी एवं बसोहली की पारंपरिक पेंटिंग को बढ़ावा देंगे तथा उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

परिवहन

1. परमिट शुल्क, टोकन टैक्स, फिटनेस शुल्क, बीमा आदि जैसे शुल्क और करों में भारी बढ़ोतरी के कारण परिवहन को नुकसान हुआ है। हमारी सरकार परिवहन क्षेत्र को राहत देने के लिए शुल्क और करों की वर्तमान दरों पर फिर से विचार करेगी।

2. हम इस क्षेत्र को उद्योग का दर्ज़ा देने की ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे।

3. वैसे ऑटो ऑपरेटर जिनका व्यवसाय टाटा मैजिक ऑपरेटर जैसे सार्वजनिक परिवहन के नए तरीकों की शुरूआत से प्रभावित हुआ है, उन वर्गों की मदद के लिए हम एक तंत्र विकसित करेंगे।

सुरक्षा

1. हमारी सरकार लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी। हम बढ़ते आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लोगों की भागीदारी से संवेदनशील क्षेत्रों में आत्मरक्षा तंत्र सहित सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करेंगे।

2. सरकार असुरक्षा को दूर करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त पिकेट्स स्थापित करेगी।

3. आतंकवाद को नियंत्रित करने के मुद्दे पर कोई समझौता न करते हुए निर्दोष लोगों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई जाएगी। बिना मुकदमे के विभिन्न जेलों में बंद लोगों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत जांच की जाएगी।

भूमि पंजीकरण

1. हम आम जनता और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित करने के बाद भूमि की बिक्री और हस्तांतरण के पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करेंगे।

2. हम लोगों को राहत देने के लिए स्टांप शुल्क दरों, अदालत शुल्क और अन्य पंजीकरण शुल्क में अभूतपूर्व वृद्धि की फिर से जांच करेंगे।

खनन

1. हमारी सरकार खनन को सख्ती से नियंत्रित करेगी, जिसके कारण पिछले दस वर्षों के दौरान अत्यधिक दोहन हुआ है, भ्रष्टाचार एवं लूट में भारी वृद्धि हुई है और रेत, बजरी, संगमरमर आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं।

2. हम किश्तवाड़ में नीलम और रियासी में लिथियम जैसे खनन के नए क्षेत्रों के नियमन में निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे।

3. हम यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे कि पारंपरिक नदी खनन अधिकारों के साथ-साथ मजदूरों, टट्टूवालों और आसपास के निवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

BHARAT
JODO
YATRA
SRINAGAR

www.inc.in | IndianNationalCongress | INCIndia